www.sanjanabharati.com
दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित
facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 टीएमसी नेताओं की निर्लज्ज टिप्पणियों से... 3 डॉक्टर्स डे: लायंस क्लब वैदेही ने सेवा और समर्पण... 4 निर्वाचित महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए 4...

वर्ष: 9 | अंक: 248 | दिल्ली, बुधवार, 2 जुलाई 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

पुनौराधाम सीता मंदिर का अगस्त में होगा शिलान्यास

बिहार (एजेन्सी)। बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगाई। राज्य के कलाकारों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का फैसला किया गया। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के विकास के लिए 882.87 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नीतीश ने एक्स पर लिखा कि मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली पुनौराधाम, सीतामढ़ी को समग्र रूप से विकसित किए जाने हेतु भव्य मंदिर सहित अन्य संरचनाओं के निर्माण की योजना को आज कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। बिहार सीएम ने आगे लिखा कि आज कैबिनेट में पुनौराधाम के समग्र विकास के लिए तैयार की गई वृहद योजना के लिए 882 करोड़ 87 लाख रू० की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना का जल्द ही कायारंभ कर दिया जाएगा। मैंने अगस्त महीने तक इसका शिलान्यास कराने का निर्देश दिया है। हमलोग पुनौराधाम, सीतामढ़ी में भव्य मंदिर निर्माण शीघ्र पूरा कराने हेतु कृतसंकल्पित हैं। इसका श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या की तर्ज पर समग्र विकास किया जाएगा। पुनौराधाम में मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण सभी देशवासियों के लिए तथा विशेष रूप से हम सभी बिहारवासियों के लिए सौभाग्य एवं गर्व की बात है।

उत्तराखंड भाजपा के दूसरी बार अध्यक्ष बने महेंद्र भट्ट

उत्तराखंड (एजेन्सी)। भाजपा के राज्यसभा सांसद और पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट एक बार फिर भाजपा उत्तराखंड के अध्यक्ष चुने गए हैं। महेंद्र भट्ट के नाम की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री और चुनाव प्रभारी हर्ष मल्होत्रा ने घोषणा की कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, बीजेपी उत्तराखंड अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, हरिद्वार सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत, पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत, टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, नैनीताल सांसद अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी को राष्ट्रीय परिषद के लिए चुना गया है। हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल को एक बार फिर बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया सोमवार सुबह 12 बजे प्रदेश भाजपा कार्यालय में शुरू हुई। चुनाव अधिकारी राजीव भारद्वाज ने सोमवार को बताया कि विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सभी भाजपा सांसदों तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर और अन्य प्रदेश पदाधिकारियों की ओर से बिंदल के नाम के तीन नामांकन पत्र दाखिल किए गए।

तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट

तमिलनाडु (एजेन्सी)। तमिलनाडु के शिवकाशी में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए शक्तिशाली विस्फोट में दो महिलाओं समेत कम से कम छह लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह विस्फोट विरुधुनगर जिले के चिन्नाकमनपट्टी के पास गोकुलेश पटाखा फैक्ट्री में हुआ। फैक्ट्री से घना धुआं उठता देखा गया और अंदर पटाखों में लगातार विस्फोट हो रहे थे। अब तक कई गंभीर रूप से घायल लोगों को बचाया जा चुका है। मंगलवार सुबह तमिलनाडु में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह विस्फोट विरुधुनगर जिले के शिवकाशी के पास चिन्ना कमानपट्टी गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ। सूत्रों के अनुसार, विस्फोट के कारण भीषण आग लग गई और फैक्ट्री से घना धुआं उठता देखा गया और अंदर से लगातार पटाखों के फटने की आवाजें आ रही थीं। विस्फोट का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गईं।

नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 77वें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। (स्त्रोत: पीआईबी)

देश के किसी भी कोने में एफआईआर दर्ज करें, 3 साल के भीतर मिलेगा न्याय-अमित शाह

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आने वाले दिनों में आपराधिक न्याय प्रणाली को बदल देंगे। इन तीन नए आपराधिक कानूनों के एक वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने कहा कि इस प्रणाली के पूर्ण कार्यान्वयन में अधिकतम तीन वर्ष लगेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के सामने सबसे बड़ी समस्या न्याय प्राप्त करने के लिए समयसीमा का अभाव है।

शाह ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसके बाद देश के किसी भी कोने में एफआईआर दर्ज करें, आपको 3 साल के भीतर न्याय मिलेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा। बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ने क्रमशः औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली। नए कानून 1 जुलाई, 2024 को लागू हुए। गृह मंत्री ने तीनों कानूनों को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सुधार करार दिया और कहा कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद सजा से बच नहीं पाएगा।

उन्होंने कहा कि न्याय निश्चित रूप से तय समय के भीतर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "नरेंद्र मोदी सरकार, आपकी चुनी हुई सरकार ने आपके लिए कानून बनाए हैं और यह आपके सभी अधिकारों की रक्षा करेगी।" 1 जुलाई, 2024 से, सभी नई एफआईआर बीएनएस के तहत दर्ज की गईं। हालांकि, पहले दर्ज किए गए मामलों को उनके अंतिम निपटारे तक पुराने कानूनों के तहत ही चलाया जाता रहा। नए कानून आधुनिक न्याय प्रणाली लेकर आए, जिसमें जीरो एफआईआर, ऑनलाइन पंजीकरण जैसे प्रावधान शामिल हैं।

धर्मशाला में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दलाई लामा से लिया आशीर्वाद

एसबी संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने धर्मशाला में दलाई लामा से भेंटकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस आत्मीय भेंट के दौरान श्री गुप्ता ने विश्व शांति, करुणा और मानवता के प्रति समर्पित परम पूजनीय दलाई लामा के शाश्वत संदेश के प्रति अपनी गहन श्रद्धा व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि ऐसे प्रेरक विचार आज के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में अत्यंत प्रासंगिक हैं। श्री गुप्ता ने इस अवसर पर परम पूजनीय दलाई लामा को दिल्ली विधानसभा पधारने का सादर आमंत्रण भी दिया, जिससे दिल्ली के जनप्रतिनिधि और नागरिक उनके दिव्य मार्गदर्शन और जीवन-दर्शन से लाभान्वित हो सकें।

2029 तक एमबीबीएस की सीटें बढाकर 3400 से अधिक करना सरकार का लक्ष्य: नायब सिंह सैनी

राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने की शिरकत

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार डॉक्टरों को बेहतर संसाधन और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2014 में जहां मेडिकल कॉलेजों की संख्या मात्र 6 थी, वहीं यह बढ़कर 15 हो गई है और 9 नए कॉलेज निमार्णाधीन हैं। इसके परिणामस्वरूप एमबीबीएस की सीटें 2014 में 700 से बढ़कर अब 2,185 हो चुकी हैं। राज्य सरकार का वर्ष 2029 तक एमबीबीएस की सीटें 3400 से अधिक करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में डेराबसी मेडिकल एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मानव सेवा की राह में डेराबस्सी मेडिकल एसोसिएशन ने उल्लेखनीय योगदान किया है। पिछले दो वर्षों से चौरसिया अस्पताल में मुफ्त डायलिसिस सेंटर चलाया जा रहा है।

श्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सा सेवा से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे मानवता के सच्चे सेवक हैं, जिनकी सेवा

भावना, समर्पण और संवेदनशीलता समाज को स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर डॉक्टर को सही संसाधन मिले और हर नागरिक को बेहतर इलाज मिले। इसी दिशा में चिकित्सा प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए प्रदेश सरकार ने पीजी की सीटें 289 से बढ़ाकर 1043 की हैं। इनके अलावा पी.जी. डिप्लोमा की भी 155 सीटें हैं। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2014 से अब तक 3,798 डॉक्टरों की भर्ती की गई है। डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु भी 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल विश्वविद्यालयों में किडनी रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई, जिसके तहत गरीब परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। हरियाणा में 'आयुष्मान भारत व चिरायु योजना में लगभग 1 करोड़ 33 लाख से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क इलाज की सुविधा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार डॉक्टर्स-डे का थीम है, 'मास्क के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल'। यह थीम हमें प्रेरित करती है कि हम डॉक्टरों की केवल पेशेवर सेवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि मानव कल्याण के लिए भी सराहना करें। उनकी जरूरतों को समझें व उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब पूरा देश घरों में बंद था, उस समय डॉक्टरों ने पीपीई किट पहनकर, परिवार से रहते हुए मरीजों के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ पर हमला करने वालों को 3 माह से 5 साल तक की सजा और 50 हजार रुपये से 2 लाख रुपये तक के जुमार्न का प्रावधान करवाया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मानव सेवा के लिए विभिन्न डॉक्टरों को सम्मानित किया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने डेराबसी मेडिकल एसोसिएशन की मैगजीन का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में चंडीगढ़ की मेयर श्रीमती हरप्रीत कौर बाबला, डेराबसी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजीव गुप्ता, सचिव डॉ. आकाश गोस्वामी सहित अन्य पदाधिकारी, बड़ी संख्या में डॉक्टर और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

पंजाब सरकार समाज के जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों की मदद कर रही है: कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़/मलोट। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश के कमजोर और पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मलोट के के.जी. पैलेस में एससी भाईचारे से संबंधित 505 परिवारों को लगभग 8 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि की कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मंत्री द्वारा आशीर्वाद योजना के अंतर्गत भी 140 लाभार्थियों को 71.40 लाख, 51,000 रुपये प्रति व्यक्ति, के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए।

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार समाज के जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अधिक से अधिक जन कल्याण को सुनिश्चित कर रही है ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि पंजाब के इतिहास में पहली बार राज्य के पिछड़े और कमजोर वर्गों को यह राहत मिली है। उन्होंने कहा कि यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि पहली बार प्रदेश का बजट आम आदमी की भलाई के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी खजाने का प्रत्येक पैसा जन कल्याण पर खर्च कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह माफी पी.एस.सी.एफ.सी. द्वारा वितरित किए गए सभी कर्जों के लिए है, जिससे एससी भाईचारे और दिव्यांग वर्ग के कर्जदारों को अत्यंत आवश्यक राहत मिली है। उन्होंने बताया कि पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम (पी.एस.सी.एफ.सी.) द्वारा 31 मार्च, 2020 तक वितरित किए गए कर्जों पर यह राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन लाभार्थियों को 'कोई बकाया नहीं' प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल, 2025 तक की गणना के अनुसार मूलधन, ब्याज और दंड ब्याज सहित पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा पी.एस.सी.एफ.सी. को वापस की जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी के बाद पी.एस.सी.एफ.सी. के नियमों के अनुसार कर्ज लेने वालों के विरुद्ध वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

इस अवसर पर जिला भलाई अधिकारी जगमोहन सिंह, कैबिनेट मंत्री के निजी सहायक अर्शदीप सिंह सिद्धू और शिंदरपाल सिंह, रमेश सिंह अरनीवाला, सुखपाल सिंह (प्रधान ट्रक यूनियन), यादविंदर सिंह (सरपंच), निर्मल सिंह (सरपंच), कुलविंदर सिंह बिढ्ढू, ज्योति (सरपंच), डॉ. साधू सिंह सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित थे।

विधायक राजेंद्र गुर्जर के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान

मरीजों को फल वितरण कर कई जगहों पर पौधारोपण भी किया

संजना भारती संवाददाता

टोंक। रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं हैं, क्योंकि रक्तदान कर हम कई लोगों की जिंदगियों को बचा सकते हैं। इसलिए सभी लोग रक्तदान कर दूसरें लोगों को भी जागरूक करनें का काम करें ताकि इमरजेंसी में रक्तदान कर किसी की मदद की जा सकें। देवली-उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर के 51वें जन्मदिन के उपलक्ष में माला, मिठाई के बजाय भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनियारा व देवली में रक्तदान शिविर सहित अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रक्तदान शिविर में कुल 134 यूनिट ब्लड का संग्रहण किया गया। उनियारा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा श्री पाल के बालाजी, कामधेनू सहित दोनों गौशालाओं, अलीगढ़ तथा देवली शहर में गौमाता को हरा चारा व गुड़ खिलाया गया।

वहीं उनियारा शहर, अलीगढ़, ककोड़, बनेठा, सोप, देवली शहर, नगरफोर्ट, नासिरदा, दूनी सहित ग्रामींण अंचलों में कई जगहों पर विधायक के जन्मदिन पर पौधारोपण किया गया। इसके बाद उनियारा के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में मरीजों तथा कच्ची बस्ती, अशोकनगर में लोगों को फल वितरित किए गए। वहीं इसके तत्पश्चात सीएचसी उनियारा व देवली शहर में ग्वाला समाज के तत्वाधान में गणेश रोड़ ग्वाला समाज धर्मशाला में बल्ड डोनेट शिविर का आयोजन किया गया जिसमें उनियारा में 74 व देवली में 60 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया।

भाजपा टीम द्वारा ब्लड डोनेट करनें वाले कार्यकर्ताओं व लोगों को प्रमाण पत्र दिए गए। उनियारा शिविर में रक्त संग्रहण राजकीय सहादत अस्पताल टोंक की टीम द्वारा किया गया जिसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ योगेश अग्रवाल, नर्सिंग ऑफिसर राजेंद्र चौधरी, पूरणमल साहू सहित अन्य चिकित्सा कार्मिक मौजूद रहें। वहीं देवली शहर में केशव ब्लड संग्रहण सेंटर देवली द्वारा किया गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर विधायक राजेंद्र गुर्जर के जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया।

विधायक के समर्थकों ने गुजरात, निवाई, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी सहित अन्य जगहों पर भी जन्मदिन के उपलक्ष में पौधारोपण किया गया। इस दौरान उनियारा में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मनीष लोदी, डॉ.रविंद्र खींची, पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर लाल ठाडा, नगरपालिका चेयरमैन मोनिका गुर्जर तथा देवली में प्रधान बनवारी लाल जाट, नगरपालिका अध्यक्ष नेमीचंद जैन, ग्वाला समाज नवयुवक मण्डल अध्यक्ष मनीष ग्वाला आदि उपस्थित रहें।

मिशन-2027: 'ड्रग फ्री दिल्ली' की दिशा में बड़ी सफलता

संजना भारती संवाददाता
मनोज कुमार प्रजापति

नई दिल्ली। मिशन-2027: 'ड्रग फ्री दिल्ली' की दिशा में बड़ी सफलता। एंटी स्नैचिंग सेल और थाना कापसहेड़ा, दक्षिण पश्चिम जिले की संयुक्त टीम द्वारा तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। लगभग 22.5 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ गांजा (बाजार मूल्य लगभग 11 लाख रुपये) गांजा ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल बरामद किया।

एंटी स्नैचिंग सेल और पुलिस स्टेशन कापसहेड़ा, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की संयुक्त टीम ने तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं 1. अनुज सैनी निवासी रोशन गार्डन, नजफगढ़, दिल्ली, उम्र 34 साल, 2. अजय श्रीवास्तव निवासी भारत विहार, दिल्ली, उम्र 25 साल और 3. रवि पांडे निवासी एलडीए कॉलोनी, लखनऊ, यूपी, उम्र 28 साल।

अमित गोयल, आईपीएस, पुलिस उप आयुक्त दक्षिण पश्चिम जिला ने बताया दिल्ली को ड्रग मुक्त बनाने के लिए

साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ड्रग पेडलर्स और सप्लायर्स के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इंस्पेक्टर हरि सिंह, प्रभारी एंटी स्नैचिंग सेल के नेतृत्व में और श्री विजय सिंह, एसीपी की देखरेख में एसआई कमल कांत, एसआई अरविंद

कुमार, एचसी राजकुमार, एचसी दिलीप, एचसी शीशराम, एचसी मुकेश, एचसी नरेंद्र, एचसी अमित कुमार, कांस्टेबल रविंदर, कांस्टेबल बबलू और कांस्टेबल सनी की एक टीम गठित की गई थी।

कांस्टेबल बबलू को समालखा, दिल्ली में ड्रग्स की आपूर्ति करने के लिए दो ड्रग आपूर्तिकताओं के आने की गुप्त सूचना मिली। तलाशी लेने पर उनके पास से कुल 3 किलो गांजा बरामद हुआ। उन्होंने पानीपत और दिल्ली-एनसीआर में ड्रग्स बेचने की बात स्वीकार की। आरोपियों के खिलाफ थाना कापसहेड़ा में एफआईआर संख्या 261/2025, धारा 20/25/29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

उनकी निशानदेही पर दिल्ली के नजफगढ़ में आरोपी अनुज सैनी के घर से 9 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। बाद में लखनऊ, यूपी से आपूर्तिकर्ता राहुल पांडे का पता लगाने के लिए माननीय न्यायालय से आरोपी अनुज सैनी का 03 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया गया। आपूर्ति के स्रोत राहुल पांडे को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई और उसे लखनऊ, यूपी भेजा गया।

दो दिनों के निरंतर प्रयासों के बाद 26.06.2025 को छापेमारी टीम ने तेजी से और चतुराई से आरोपी रवि पांडे निवासी एलडीए कॉलोनी, लखनऊ, यूपी, उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया, जिसके उपरोक्त आवास से 10.416 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। आगे की जांच जारी है।

सम्पादकीय

डिजिटल इंडिया का एक दशक

दस साल पहले, हमने एक ऐसे क्षेत्र में पूर्ण विश्वास के साथ ऐसी यात्रा शुरू की थी, जहां पहले कोई नहीं गया था। जहाँ दशकों तक यह संदेह किया गया कि भारतीय तकनीक का उपयोग कर पाएंगे की नहीं, हमने उस सोच को बदला और भारतीयों की तकनीक का उपयोग करने की क्षमता पर विश्वास किया। जहाँ दशकों तक सिर्फ यह सोचा गया कि तकनीक का उपयोग अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा करेगा, हमने उस मानसिकता को बदला और तकनीक के माध्यम से उस खाई को खत्म किया। जब नीयत सही होती है, तो नवाचार वंचितों को सशक्त करता है। जब दृष्टिकोण समावेशी होता है, तो तकनीक हाशिए पर खड़े लोगों के जीवन में परिवर्तन लाती है। यही विश्वास डिजिटल इंडिया की नींव बना-एक ऐसा मिशन जो सभी के लिए पहुंच को लोकतांत्रिक (आसान) बनाने, समावेशी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए शुरू हुआ। 2014 में, इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, डिजिटल साक्षरता कम थी, और सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन पहुंच बेहद सीमित थी। कई लोगों को संदेह था कि भारत जैसा विशाल और विविध देश वास्तव में डिजिटल बन सकता है या नहीं। आज, इस प्रश्न का उत्तर डेटा और डैशबोर्ड में नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के जीवन के माध्यम से दिया जा चुका है। शासन से लेकर शिक्षा, लेन-देन और निर्माण तक, डिजिटल इंडिया हर जगह है। 2014 में भारत में लगभग 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज यह संख्या बढ़कर 97 करोड़ से अधिक हो चुकी है। 42 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का 11 गुना है, अब दूरस्थ गांवों को भी जोड़ रही है। भारत का 5G रोलआउट विश्व में सबसे तेज रोलआउट्स में से एक है, और मात्र दो वर्षों में 4.81 लाख बेस स्टेशंस स्थापित किए गए हैं। हाई-स्पीड इंटरनेट अब शहरी केंद्रों से लेकर अग्रिम सैन्य चौकियों तक जैसे गलवान, सियाचिन और लद्दाख पहुँच चुका है। इंडिया स्टैक, जो हमारा डिजिटल बैकबोन है, ने UPI जैसे प्लेटफार्म को सक्षम बनाया है, जो अब सालाना 100 बिलियन से अधिक लेन-देन करता है। विश्व में होने वाले कुल रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन में से लगभग आधे भारत में होते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे नागरिकों को हस्तांतरित की गयी है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई और 3.48 लाख करोड़ रुपये की लीकेज रोकी गई है। स्वामित्व जैसी योजनाओं ने 2.4 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड्स जारी किए हैं और 6.47 लाख गांवों को मैप किया है, जिससे वर्षों से चली आ रही भूमि संबंधी अनिश्चितता का अंत हुआ है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था अब पहले से कहीं अधिक MSMEs और छोटे उद्यमियों को सशक्त बना रही है। ONDC (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) एक क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म है जो विक्रेताओं और खरीदारों के विशाल बाजार से सीधा संपर्क स्थापित कर नए अवसरों की खिड़की खोलता है। GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) आम आदमी को सरकार के सभी विभागों को सामान और सेवाएं बेचने की सुविधा देता है। इससे न केवल आम नागरिक को एक विशाल बाजार मिलता है बल्कि सरकार की बचत भी होती है। कल्पना कीजिए: आप मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं। आपकी क्रेडिट योग्यता को अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के माध्यम से आंका जाता है। आपको लोन मिलता है, आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। आप GeM पर पंजीकृत होते हैं, स्कूलों और अस्पतालों को सप्लाई करते हैं और फिर ओएनडीसी के माध्यम से इसे और बड़ा बनाते हैं। ओएनडीसी ने हाल ही में 20 करोड़ लेन-देन का आंकड़ा पार किया है- जिसमें पिछले 10 करोड़ सिर्फ 6 महीनों में हुए हैं। बनारसी बुनकरों से लेकर नागालैंड के बांस शिल्पियों तक, अब विक्रेता बिना बिचौलियों के पूरे देश में ग्राहक तक पहुँच रहे हैं। GeM ने 50 दिनों में एक लाख करोड़ रुपये का GMV पार किया है, जिसमें 22 लाख विक्रेता शामिल हैं, जिनमें 1.8 लाख से अधिक महिला संचालित MSMEs हैं, जिन्होंने 46,000 करोड़ रुपये की आपूर्ति की है। भारत का डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI)-जैसे आधार, CoWIN, डिजिलॉकर, फास्टैग, पीएम-WANI और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन- को अब वैश्विक स्तर पर पढ़ा और अपनाया जा रहा है।

जयंती

मोहम्मद अजीज

जन्म-2 जुलाई, 1954, पश्चिम बंगाल; मृत्यु-27 नवंबर, 2018, मुंबई, महाराष्ट्र) भारत के प्रसिद्ध पार्श्वगायकों में से एक थे, जिन्होंने मुख्यत: बंगाली, ओड़िया और हिन्दी फिल्मों में गाने गाये। उन्होंने कोलकाता के गालिब रेस्टोरेंट में एक गायक के तौर पर अपना कॅरियर शुरू किया था। साल 1984 में वे मुंबई आए थे। उनकी पहली हिंदी फिल्म 'अम्बर' थी, जो 1984 में रिलीज हुई। मोहम्मद अजीज ने पहली बार अमिताभ बच्चन की फिल्म 'मर्द' के लिए 'मर्द टांगे वाला' गीत गाया था। उन्हें 80 और 90 के समय में मोहम्मद रफी का उत्तराधिकारी कहा जाता था। मोहम्मद अजीज ने अलग-अलग भाषाओं में 20 हजार से अधिक गाने गाए। 'खुदगर्ज' फिल्म का मशहूर गाना आपके आ जाने से...अजीज सहाब ने ही गया था, जिसे अभिनेता गोविंदा और अभिनेत्री नीलम पर फिल्माया गया था। मोहम्मद अजीज ने लता मंगेशकर, आशा भोंसले, कविता कृष्णमूर्ति जैसी मशहूर गायिकाओं के साथ युगल गीतों में भी अपनी आवाज दी।

पुण्यतिथि

यूसुफ मेहरअली

जन्म-23 सितंबर, 1903, मुम्बई, महाराष्ट्र; मृत्यु-2 जुलाई, 1950) स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक थे। यूसुफ ने मजदूर और किसान संगठन को मजबूत कराने में योगदान दिया तथा इसी कारण स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आठ बार जेल में जाना पड़ा। मेहरअली कांग्रेस सोशलिस्ट के संस्थापकों में से एक थे।

कल मिलेंगे

पूजा के समय पत्नी ने पति से पूछा
पत्नी-सुनो जी आपको आरती याद है न?
पति-हां...वो पतली सी, वही न?
इसके बाद भगवान की बाद में, पति की 'पूजा' पहले हुई.

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHIN/2016/70240

Phone No.: 9871221635

E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com

(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

टीएमसी नेताओं की निर्लज्ज टिप्पणियों से उठा विवाद

अत्याचारियों के लिये ही त्वरित न्याय और सख्त सजा जरूरी है लेकिन जन-प्रतिनिधि की निर्लज्ज बयानबाजी भी अपराध के दायरे में होनी चाहिए। आजीवन शोषण, दमन, अत्याचार, अवांछित बर्ताव और अपमान की शिकार रही भारतीय नारी को अब ऐसे और नये-नये तरीकों से कब तक जहर के घूंट पीने को विवश होना होगा। अत्यंत विवशता और निरीहता से देख रही है वह यह क्रूर अपमान, यह वीभत्स अनादर, यह दूषित व्यवहार एवं संकुचित न्याय

-ललित गर्ग

कोलकाता में कानून की एक छात्रा से सामूहिक दुराचार-गैंगरेप का मुद्दा एक बार फिर पश्चिम बंगाल में जितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने लगा है उतना ही बड़ा नारी उत्पीड़न का मुद्दा बनकर उभर रहा है। इस मामले में पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं की अनर्गल एवं निर्लज्ज टिप्पणी स्त्री की मयार्दा, सम्मान एवं अस्मिता के खिलाफ शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण व संवेदनहीन प्रतिक्रिया है। इन नेताओं ने गैंगरेप मामले पर विवादित बयान से राज्य एवं देश में भारी जनाक्रोश पैदा हो गया था। विशेषतः राजनेताओं के बयानों एवं सोच में एक बार फिर शर्मनाक ढंग से पीड़िता पर दोष मढ़ने की बेशर्म कोशिश की गई है। इस मामले में सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी अन्दर एवं बाहर दोनों मोर्चों पर घिरती हुई नजर आ रही है। जहां इस मामले में पार्टी के अन्दर गुटबाजी एक बार फिर सामने आयी है, वहीं भाजपा आक्रामक रूप से ममता सरकार को घेर रही है। टीएमसी की महिला नेत्री महुआ मोइत्रा टीएमसी नेताओं कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा के उन बयानों पर निराशा व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि इन राजनेताओं के बयान में स्त्री-द्वेष पार्टी लाइन से परे है।

यह एक बदतर स्थिति है कि जिस पार्टी के नेताओं ने ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिए हैं, उस पार्टी की सुप्रीमो एक महिला ही है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि ममता बनर्जी जैसी तेजतर्रार मुख्यमंत्री के शासन और नेतृत्व के वर्षों के दौरान टीएमसी के भीतर नारी सम्मान एवं अस्मिता को लेकर संवेदनशीलता लाने और मानसिकता में बदलाव लाने के प्रयास विफल होते नजर आ रहे हैं। अकसर महिलाएं और महिला राजनेता पुरुष नेताओं के हाथों अश्लील, अभद्र और तौहीन भरी टिप्पणओं की शिकार होती रही हैं। ऐसे बयानों के बावजूद अकसर ये राजनेता किसी कठोर कार्रवाई की बजाय हल्की फुल्की फटकार के बाद बच निकलते हैं। ये बयान कभी महिलाओं की बॉडी शेमिंग करते नजर आते हैं तो कभी बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को मामूली बताने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही ये चिन्ताजनक संदेश भी जाता है कि महिलाओं के बारे में हल्के और आपत्तिजनक बयान देना विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के लिये सामान्य बात है।

जब किसी देश की बेटियां न्याय का अध्ययन कर रही हों और वहीं उनके साथ अन्याय की पराकाष्ठा हो तो यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि पूरे समाज, व्यवस्था और सोच के लिए एक जघन्य आइना बन जाती है। प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की घटना ने न केवल राजनीतिक सोच एवं कानून के मंदिरों को शर्मसार किया है, बल्कि हर संवेदनशील मन को झकझोर दिया है। पीड़िता एक लॉ कॉलेज में अध्ययनरत छात्रा थी, जो अपने उज्ज्वल भविष्य के सपनों के साथ शिक्षा के पथ पर अग्रसर थी। घटना की रात वह अपने कुछ परिचितों के साथ बाहर थी, जिनमें से ही कुछ ने उसकी अस्मिता को रौंद डाला। उसे नशा दिया गया और फिर सुनसान स्थान पर ले जाकर कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है, लेकिन सवाल यह है कि जब कानून पढ़ने वाली लड़की खुद असुरक्षित है, तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? क्या यह कानून की शिक्षा देने वाली संस्थाओं एवं शासन करने वाली सत्ताओं के लिए आत्ममंथन का समय नहीं है? ऐसी घटनाओं पर निर्भया कांड के बाद बने कानूनों का सख्ती से पालन हो। रेप को सिर्फ एक जुर्म नहीं, राष्ट्रीय आपदा माना जाए, और उसकी रोकथाम के लिए शिक्षा, संस्कार और तकनीकी सुरक्षा साधनों को प्राथमिकता दी जाए। कोलकाता की लॉ छात्रा की यह दर्दनाक घटना हमें चेताती है कि केवल कानून बना लेना काफी नहीं, जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक बेटियां असुरक्षित रहेंगी। यह केवल एक छात्रा की लड़ाई नहीं, बल्कि हर बेटी की सुरक्षा की लड़ाई है। न्याय तब होगा जब ऐसी घटनाएं रुकेंगी और उसके लिए हमें मिलकर लड़ना होगा।

सबसे दुखद पहलू यह है कि अनेक बार ऐसी घटनाओं में समाज चुप रहता है, पीड़िता को दोषी ठहराने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया पर तंज, मीडिया ट्रायल और व्यक्तिगत चरित्रहनन जैसी बातें पीड़िता को न्याय से अधिक पीड़ा देती हैं। पीड़िता के लिये यह पीड़ा तब और बढ़ जाती है जब उनके जन-प्रतिनिधि निर्लज्ज बयानबाजी करते हैं। विडंबना यह है कि पीड़िता के प्रति निर्लज्ज बयानबाजी अकेले पश्चिम बंगाल का ही मामला नहीं है, देश के अन्य राज्यों में भी ऐसी संवेदनहीन टिप्पणियां सामने आती रही हैं। यदि इक्कीसवीं सदी के खुले समाज में हम महिलाओं के प्रति संकीर्णता की दृष्टि से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो इसे विडंबना ही कहा जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कि ये वे लोग हैं जिन्हें जनता अपना नेता मानती है और लाखों लोग उन्हें चुनकर जनप्रतिनिधि संस्थाओं में कानून बनाने व व्यवस्था चलाने भेजते हैं। देश में बढ़ रही यौन-शोषण, रेप एवं नारी दुराचार की घटनाओं को देखते हुए जन-प्रतिनिधियों को ज्यादा संवेदनशील होने की अपेक्षा की जाती है। बड़ा प्रश्न है कि आखिर किसी राजनेता को हर महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार और यौन शोषण को असंवेदनशील तरीके से देखने की छूट क्यों एवं कैसे मिल जाती है।

भारत ही ऐसा देश है, जहां महिलाओं की अस्मिता एवं अस्तित्व को तार-तार करने वाले नेताओं के निर्लज्ज बयानों के बावजूद उन पर कोई ठोस, सख्त एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती। जबकि विश्व के अन्य देशों में ऐसा नहीं है। जैसे 2017 में ब्रिटेन के एक पार्षद के सामान्य से बयान पर अच्छा खासा बवाल मचा था। पार्षद ने सांसद का चुनाव लड़ रही एक गर्भवती महिला राजनेता के बारे में कह दिया था, वो गर्भवती हैं और उनका समय तो नैपी बदलने में ही बीत जाएगा, वो आम लोगों की आवाज क्या उठाएंगी? इसके लिए पार्षद को माफी मांगनी पड़ी। ब्रिटेन जैसे कई देशों में अकसर ऐसे बयानों पर कार्रवाई होती है। मिसाल के तौर पर 2017 में ही यूरोपियन संसद के एक सांसद ने बयान दिया था कि महिलाओं को कम पैसा मिलना चाहिए क्योंकि वो कमजोर, छोटी और कम बुद्धिमान होती हैं। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था और उन्हें मिलने वाला भत्ता भी बंद हो गया था।

कोलकाता की लॉ छात्रा मामले में टीएमसी नेताओं की टिप्पणियां निस्संदेह निंदनीय हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं व कार्यकताओं द्वारा भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जानी चाहिए। ममता बनर्जी के सामने एक और चुनौती है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार- हत्याकांड और उसके बाद देश भर में उपजा आक्रोश अभी भी यादों में ताजा है। निस्संदेह, केवल टिप्पणियों से पार्टी को अलग कर देना ही पर्याप्त नहीं है। सार्वजनिक जीवन में नारी सम्मान एवं जीवन-मूल्यों के खिलाफ जाने वाले लोगों के लिये परिणाम तय होने चाहिए। अन्यथा समाज में ये संदेश जाएगा कि ऐसे कुत्सित प्रयासों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है। किसी अपराध की रोकथाम अच्छे शासन की अनिवार्य शर्त बनना चाहिए लेकिन जब कोई अपराध होता है तो प्रभावी प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। टीएमसी दोनों ही मामलों में विफल प्रतीत होती है। ऐसे मामलों में अत्याचार करने वालों की ही भांति अत्याचार का समर्थन करने वाले दोषी है।

अत्याचारियों के लिये ही त्वरित न्याय और सख्त सजा जरूरी है लेकिन जन-प्रतिनिधि की निर्लज्ज बयानबाजी भी अपराध के दायरे में होनी चाहिए। आजीवन शोषण, दमन, अत्याचार, अवांछित बर्ताव और अपमान की शिकार रही भारतीय नारी को अब ऐसे और नये-नये तरीकों से कब तक जहर के घूंट पीने को विवश होना होगा। अत्यंत विवशता और निरीहता से देख रही है वह यह क्रूर अपमान, यह वीभत्स अनादर, यह दूषित व्यवहार एवं संकुचित न्याय। न्याय एवं राजनीति की चौखट पर भी उसके साथ दोयम दर्जा एवं दुराग्रहपूर्ण सोच बदलना सर्वोच्च प्राथमिकता हो। यदि हम सच में नारी के अस्तित्व एवं अस्मिता को सम्मान देना चाहते हैं तो ईमानदार स्वीकारोक्ति, पड़ताल एवं निष्पक्ष न्याय से ही यह संभव होगा।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

क्यों नहीं पहुंच पातीं सरकारें घरों की दहलीज तक?

शिक्षा के साथ-साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी नौकरियों में भी ऐतिहासिक कदम उठाए गए। वर्ष 2013 से पुलिस भर्ती में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। 2016 से सभी प्रकार की सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है, और प्राथमिक शिक्षक नियोजन में तो 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें सशक्त किया गया है

-संजीव कुमार मिश्र

भारतीय राजनीति में महिलाओं के सशक्तीकरण की बातें खूब होती हैं। चुनावी घोषणापत्रों में उनके लिए वादे भी किए जाते हैं, परंतु चुनाव बीतते ही वायदों पर धूल की परत जम जाती है। शायद ही कोई जनप्रतिनिधि उनके दुख-दर्द को सुनने, उनकी अपेक्षाओं को समझने के लिए घर की दहलीज तक जाता हो?

यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे देश के अधिकांश राज्यों में महिलाओं ने जिया है। लेकिन तारीफ करनी होगी बिहार की जिसने इस परिपाटी को तोड़कर एक नई मिसाल कायम की है। एक ऐसा प्रदेश, जिसने दशकों तक महिलाओं को पुरुषों के निर्देशों पर मताधिकार का प्रयोग करते देखा, आज वही महिला सशक्तीकरण की एक ऐसी नई इबारत लिख रहा है, जो देश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन चुकी है।

इस परिवर्तनकारी यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव 'महिला संवाद' कार्यक्रम है, जिसे विगत 18 अप्रैल से प्रदेश में ग्राम स्तर पर शुरू किया गया। यह पहल केवल एक सरकारी कवायद नहीं, बल्कि महिलाओं को केंद्र में रखकर सामाजिक बदलाव को गति देने का एक सशक्त माध्यम है। यह कार्यक्रम प्रदेश की बेटियों, माताओं और बहनों की आवाज को गंभीरता से सुनने, समझने और भविष्य की नीतिगत व प्रशासनिक पहलों को आकार देने का एक महत्त्वपूर्ण मंच बन गया है। यह संतोष का विषय है कि अब तक 38 जिलों में 52,468 महिला संवाद कार्यक्रमों का सफल आयोजन हो चुका है, जिसमें कुल 1 करोड़ 13 लाख से अधिक महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। यह संख्या इस बात का भी जीवंत प्रमाण है कि प्रदेश की महिलाएं अब अपनी आवाज उठाने और सरकार से सीधे जुड़ने को लेकर कितनी उत्सुक और जागरूक हैं। दरभंगा से लेकर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, नालंदा और वैशाली तक, हर जगह महिलाओं ने बेबाकी से अपनी बात रखी है। उन्होंने नीति-निमार्ताओं को यह समझने का अवसर दिया है कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में आगे किन प्राथमिकताओं के साथ कदम बढ़ाए जाएं।

महिला संवाद की यह पृष्ठभूमि आकस्मिक नहीं है। नीतीश कुमार के कार्यकाल को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि सबसे पहले, लड़कियों में शिक्षा की अलख जगाने पर जोर दिया गया। जहां वर्ष 2000 के आसपास बिहार में लड़कियाँ सरकारी स्कूलों में कम जाती थीं, वहीं वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरूआत ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इस योजना ने लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, जिससे वे दूर-दराज के गांवों से भी साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने लगीं। इसकी सफलता ने देश के अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया।

शिक्षा के साथ-साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी नौकरियों में भी ऐतिहासिक कदम उठाए गए। वर्ष 2013 से पुलिस भर्ती में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। 2016 से सभी प्रकार की सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है, और प्राथमिक शिक्षक नियोजन में तो 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें सशक्त किया गया है।

महिलाओं के सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन में 'जीविका' स्वयं सहायता समूह का गठन भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से ऋण लेकर शुरू की गई 'जीविका' ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए वरदान साबित हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा इन महिलाओं को दिया गया 'जीविका दीदी' नाम आज एक पहचान बन चुका है।

वर्तमान में, बिहार में 10 लाख 64 हजार स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिनसे 1 करोड़ 35 लाख से अधिक जीविका दीदियाँ जुड़ी हैं। जीविका से जुड़कर ये महिलाएं लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर अपने और अपने समुदाय के जीवन स्तर में सुधार ला रही हैं।

'महिला संवाद' कार्यक्रम में प्रदेश की महिलाओं ने कई महत्त्वपूर्ण और व्यवहारिक मांगें रखी हैं, जो उनकी दूरदृष्टि और आकांक्षाओं को दशार्ती हैं। उनकी सबसे प्रमुख मांग स्वरोजगार से जुड़ी है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों के लिए सस्ते ब्याज दरों पर ऋण और 'जीविका दीदी की रसोई' व 'जीविका दीदी हाट' जैसी पहल शामिल हैं। कृषि क्षेत्र में प्रखंड स्तर पर राइस मिलों की स्थापना, वेजिटेबल मार्ट, किसान सम्मान निधि में वृद्धि और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की मांगें भी मुखरता से उठी हैं।

बुनियादी सुविधाओं के लिए 'जीविका भवन', लाइब्रेरी और पंचायत स्तर पर बैंकिंग सुविधाओं की मांग की गई है। सामाजिक सुधारों में शराबबंदी की तर्ज पर गुटखा, सिगरेट और तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध, और सुरक्षा के लिए महिला पुलिस चौकी, हेल्प डेस्क तथा प्रखंड स्तर पर महिला थाना बनाने की मांगें भी प्रमुखता से रखी गई हैं। यह आशा की जाती है कि सरकार इन मांगों पर शीघ्रता से विचार कर अपेक्षित निर्णय लेगी। यह संतोषजनक है कि बिहार सरकार की नीतियों और योजनाओं के कारण प्रदेश में महिला सशक्तीकरण का एक स्वर्णिम दौर शुरू हुआ है। 2005 से पूर्व और उसके बाद बिहार में आए इस सकारात्मक बदलाव को आज हर स्तर पर देखा और महसूस किया जा रहा है। आंकड़े स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं: 93.11% महिलाएं आज खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, 91.73% घरों में घरेलू हिंसा कम हुई है, और 87.75% महिलाएं खुद को आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत मानती हैं।

आज बिहार में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी लगन और मेहनत से अपना मुकाम बना रही हैं। यह बदलता बिहार है, जहाँ की बेटियां अब सिर्फ घर की चौखट के भीतर नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन और नीति-निर्माण में भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विकसित बिहार के निर्माण में महिलाओं की यह बढ़ती भागीदारी न केवल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि जब महिलाओं को अवसर और मंच मिलता है, तो वे न केवल अपनी बल्कि पूरे समाज की तकदीर बदलने की क्षमता रखती हैं।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

जमीन में गड्ढा कर पाकिस्तान पर हमला करेगा भारत!

(एजेन्सी)।

भारत ने एक ऐसा ऑपरेशन शुरू कर दिया है जिसके जरिए पाकिस्तान जैसे आतंकी देश में गड्ढा खोदकर हमले किए जा सकते हैं। भारत ने इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस बात की पूरी गारंटी है कि भारत जो करने जा रहा है, उसमें 100 प्रतिशत सफलता मिलेगी। दरअसल, भारत एक ऐसा बम बना रहा है जो जमीन में सैकड़ों फीट नीचे घुसकर परमाणु अड्डे उड़ाकर आ सकता है। भारत को इजरायल और ईरान जंग से बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस जंग में वर्षों बाद अमेरिकी सेना ने सीधा हमला किया। इजरायल ईरान जंग से सबसे अहम सीख ये मिली कि अब एयर डिफेंस सिस्टम और बैलेस्टिक मिसाइलों का जमाना आ गया है। भारत को दूसरी बड़ी सीख ये मिली कि दुश्मन देश के रिएक्ट करने से पहले ही उसके परमाणु बमों को नष्ट करना होगा। खासकर पाकिस्तान जैसे आतंकी देश ने जो जमीन के नीचे बने न्यूक्लियर फैसिलिटी में छिपा रखे हैं। ईरान के परमाणु फैसिलिटी को टारगेट करने के लिए अमेरिका की तरफ से इस्तेमाल किए गए बंकर बस्टर बम की चर्चा पूरी दुनिया में खूब हुई। बी2 बॉम्बर्स के अमेरिका द्वारा इस्तेमाल के बाद अब बंकर बस्टर जैसे हाईटेक बमों को लेकर दुनिया भर के देश अपनी रक्षा क्षमताओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। भारत ने अपनी सामरिक शक्ति को एक नई दिशा में मोड़ते हुए 'अग्नि-5' अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का पारंपरिक (नॉन-न्यूक्लियर) संस्करण विकसित करना शुरू कर दिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) इस मिसाइल को 7500 किग्रा तक भारी बंकर बस्टर वारहेड के साथ तैयार कर रहा है। ये बम 60 मीटर से अधिक गहराई तक प्रहार करने में सक्षम हैं। हालांकि, ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी करीब 80 मीटर गहराई में बनी है, जो सामान्य बमों से अप्रभावित रहती है। भारत की मिसाइल ज्यादा गहराई तक करेगी वार डीआरडीओ की नई मिसाइल 80 से 100 मीटर तक जमीन के अंदर घुसकर हमला करने में सक्षम होगी, जो अमेरिका के जीबीयू-57 की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकती है। जहां जीबीयू-57 को भारी बमवर्षक विमानों द्वारा दागा जाता है, भारत का संस्करण मिसाइल आधारित होगा, यह अधिक तेज, सटीक और जोखिममुक्त रणनीति मानी जा रही है।

रूस के सैन्य प्रतिष्ठान में व्याप्त भ्रष्टाचार, पूर्व उप रक्षा मंत्री को 13 साल की जेल

(एजेन्सी)।

रूस के सैन्य प्रतिष्ठान में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले एक बड़े घटनाक्रम में पूर्व उप रक्षा मंत्री तिमुर इवानोव को मंगलवार को गबन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी ठहराया गया। उन्हें 13 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इवानोव की सजा कथित सैन्य भ्रष्टाचार की चल रही जांच में अब तक का सबसे प्रमुख परिणाम है, जिसमें पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के करीबी संबंध रखने वाले कई शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं। इस घोटाले ने अपने पैमाने और सैन्य नेतृत्व से सीधे संबंध के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित किया है।

49 वर्षीय इवानोव को 2016 में उप रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था और उन्होंने सैन्य निर्माण परियोजनाओं के साथ-साथ सेना के लिए संपत्ति प्रबंधन, आवास और चिकित्सा सहायता की देखरेख की थी। वह अपनी भव्य जीवनशैली के लिए जाने जाते थे, जिससे मॉस्को में कई लोग नाराज थे, ठीक उसी तरह जैसे यूक्रेन में लड़ाई ने रूसी सैन्य संगठन और आपूर्ति में स्पष्ट कमियों को उजागर किया था, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध के मैदान में असफलताएँ मिलीं।

इवानोव, जो अप्रैल 2024 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में है, को मॉस्को सिटी कोर्ट ने 3.9 बिलियन रूबल (लगभग 50 मिलियन अमरीकी डॉलर) के गबन का दोषी ठहराया, इन आरोपों से उसने इनकार किया।

अदालत ने उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जिसमें बेशकीमती अचल संपत्ति और पुरानी कारों का संग्रह शामिल था। इवानोव के वकीलों ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। यूक्रेन में मास्को की सैन्य कार्रवाई में उसकी भूमिका के लिए इवानोव को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

स्मृति मंधाना की टी20 रैंकिंग में बड़ी छलांग

(एजेन्सी)।

आईसीसी ने अपनी ताजा टी20 रैंकिंग का ऐलान किया है। इस दौरान भारतीय स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने एक बार खुद को साबित कर दिया है। मंधाना को दुनियाभर में बेहतरीन बल्लेबाजों के रूप में गिना जाता है। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में 62 गेंदों में 112 रन की तूफानी पारी खेलने के बाद मंधाना आईसीसी की महिला टी20 इंटरनेशनल बैटर रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। ये मंधाना का टी20 में पहला शतक था, जो उन्होंने अपने 149वें मैच में लगाया। 12 साल बाद उन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में शतक का सूखा खत्म किया। उनकी पारी की मदद से भारत ने इंग्लैंड को पहले टी20 मैच में 97 रन से हराया। इसी पारी के दम पर मंधाना को रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ। मंधाना के पास 771 रेटिंग अंक है और वह उन्होंने नई करियर-सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है। स्मृति मंधाना नंबर 1 पर काबिज बेथ मूनी से महज 23 अंक ही पीछे हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में 20 रन की पारी खेलने वाली भारतीय सलामी बल्लेबाज शैफाली वर्मा को भी फायदा हुआ है। शेफाली भी एक स्थान ऊपर बढ़कर 13वें पायदान पर पहुंच गई है।

वहीं, उनकी साथी खिलाड़ी हरलीन देओल ने 43 रन की अपनी तेजतर्रार पारी के बाद बल्लेबाजों की रैंकिंग में फिर से एंट्री की और वह संयुक्त रूप से 86वें स्थान पर हैं। गेंदबाजों की बात करें तो, इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल ने नॉटिंघम में खेले गए मुकाबले में भारत के तीन विकेट अपने नाम किए थे। इसके साथ ही दाएं हाथ की गेंदबाज ने दो स्थान की छलांग लगाकर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ चौथा स्थान हासिल किया। पाकिस्तान की स्पिनर सादिया इकबाल टी20 गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप पर काबिज हैं।

विनेश फोगाट ने बेटे को दिया जन्म

रेसलर और जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने अपने जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा है। उन्होंने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया। विनेश ने 6 मार्च 2025 को इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्ट के जरिए दी थी। उन्होंने अपने पति सोमवीर राठी के साथ एक खूबसूरत फोटो शेयर की थी। विनेश के ससुर राजपाल राठी ने बताया कि विनेश फोगाट की डिलीवरी ऑपरेशन के जरिए हुई और पूरी तरह सुरक्षित रही, मां बेटा दोनों स्वस्थ हैं। बता दें कि, विनेश और सोमवीर राठकी शादी 14 दिसंबर 2018 को हुई थी। सोमवीर राठी भी पूर्व भारतीय पहलवान हैं। दोनों की पहली मुलाकात 2011 में हुई थी। तब दोनों रेलवे में नौकरी करते थे। धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोनों एक-दूसरे को दिल दे बैठे।

सस्ता हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर

(एजेन्सी)।

तेल विपणन कंपनियों ने घोषणा की कि 19 किलोग्राम वाले एलपीजी वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमतों में 58.50 रुपये की कमी की जाएगी, जिससे नई दर 1,665 रुपये हो जाएगी, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। संशोधित कीमतें रेस्तरां, होटल और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बहुत जरूरी राहत प्रदान करेंगी जो अपने दैनिक कार्यों के लिए 19 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट के अनुसार, एलपीजी की नई कीमतें 1 जुलाई 2025 से लागू हो गई हैं। प्रमुख शहरों में 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम कर दी गई है, जिससे वाणिज्यिक उपयोगकताओं को राहत मिली है।

संशोधित कीमतों का विवरण इस प्रकार है: दिल्ली: 1,723.50 रुपये से घटकर 1,665.00 रुपये-58.50 रुपये की कटौती

कोलकाता: 1,826.00 रुपये से घटकर 1,769.00 रुपये - 57.00 रुपये की कटौती

मुंबई: 1,674.50 रुपये से घटकर 1,616.50 रुपये - 58.00 रुपये की कटौती

चेन्नई: 1,881.00 रुपये से घटकर 1,823.50 रुपये - 57.50 रुपये की कटौती

गौरतलब है कि वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में यह लगातार चौथी बार मासिक कटौती है। इससे पहले जून में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 24 रुपये की कटौती की गई थी। उससे पहले एक मई को कीमतों में 14.50 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई थी और अप्रैल में कीमतों में 41 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई थी।

पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती

(एजेन्सी)। 01 जुलाई को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती अपना 33वां जन्मदिन मनाई। वह अपने करियर से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। रिया चक्रवर्ती को लोग उनकी फिल्मों और एक्टिंग के लिए कम और सुशांत सिंह राजपूत की वजह से ज्यादा जानते हैं। वह एक मॉडल, वीजे और एक्ट्रेस रही हैं। रिया चक्रवर्ती ने तेलुगु सिनेमा से अपनी शुरूआत करने के बाद बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है। तो आइए जानते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर रिया चक्रवर्ती के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में...कर्नाटक के बेंगलुरू में 01 जुलाई 1992 को रिया चक्रवर्ती का जन्म हुआ था। यह एक आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि इनके पिता इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। रिया ने अपने करियर की शुरूआत टीवी से की। उन्होंने साल 2009 में एमटीवी टीन दिवा में हिस्सा लिया था। जहां वो फर्स्ट रनरअप रही थीं। इसके बाद उन्होंने एमटीवी वीजे के रूप में काम किया। इस दौरान रिया ने कुछ एक टीवी शो भी होस्ट किए। साल 2012 में रिया चक्रवर्ती ने तेलुगु फिल्म 'तुनीगा तुनीगा' से अपने करियर की शुरूआत की। इस फिल्म में रिया के साथ सुमंथ अश्विन मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में साल 2013 में आई फिल्म 'मेरे डैड की मारूति से' डेब्यु किया था।

फिल्में: रिया चक्रवर्ती ने साल 2014 में 'सोनाली केबल', साल 2017 'बैंक चोर', साल 2017 में 'हाफ गर्लफ्रेंड', साल 2017 में 'दोबारा' और साल 2018 'जलेबी' जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि इनमें से किसी भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिली। वहीं साल 2018 के बाद तीन साल के लंबे गैप के बाद एक्ट्रेस साल 2021 में आई फिल्म 'चेहरे' में नजर आई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी प्रमुख भूमिका में नजर आए थे। लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी।

डॉक्टर्स डे: लायंस क्लब वैदेही ने सेवा और समर्पण के लिए डॉ. सरोज सिंह और डॉ. आशुतोष दिनेंद्र को किया सम्मानित

संजना भारती संवाददाता

सिवान। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस (डॉक्टर्स डे) पर लायंस क्लब वैदेही ने मंगलवार को सेवा और समर्पण के लिए सिवान के दो डॉक्टरों को सम्मानित किया। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर सिवान की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सरोज सिंह और युवा डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र को लायंस क्लब वैदेही की टीम ने उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। दिल्ली होने के कारण डॉ. सरोज सिंह का सम्मान उनकी बेटी डॉ. ऋचा सिंह ने ग्रहण किया। डॉ. सरोज सिंह ने वीडियो संदेश जारी कर आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम के दौरान लायंस क्लब वैदेही की सेक्रेटरी लायन मोनिका शेखर, लायन नाजिया, लायन अंजना, लायन अमृता, लायन सबिता, लायन अचला, लायन डॉ. सौरव सिंह, डॉ. अंजू, लायन दुर्जय, लायन सुधांशु, लायन अनमोल आदि उपस्थिति रहे।

प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेष डॉ. सरोज सिंह मोतिहारी की सिविल सर्जन व स्वास्थ्य विभाग की अपर निदेशक रही हैं और वह हमेशा गरीब और जरूरतमंदों की सेवा को तत्पर रही। उनके हॉस्पिटल डॉ. सरोज सिंह मैटरनिटी सेंटर में हर महीने की 7 तारीख को निःशुल्क मेडिकल कैंप लगता है। डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल हैं और वे जुलाई 2017 से सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। लायंस क्लब वैदेही की सेक्रेटारी मोनिका शेखर ने कहा कि डॉक्टर न केवल बीमारियों का इलाज करते हैं, बल्कि आशा, विश्वास और जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। एक डॉक्टर विषम परिस्थितियों में हमेशा सबसे आगे खड़े होते हैं। वे कई बार खुद की परवाह किए बिना अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की सेवा करते हैं।

भारत में हर साल 1 जुलाई को देश के चिकित्सा पेशेवरों के प्रति आभार व्यक्त करने और उनका सम्मान करने के लिए डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में 1991 से भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है।

डॉक्टर्स डे के अवसर पर आंख जांच शिविर आयोजित

एसबी ब्यूरो

बरौनी(बेगूसराय)। मंगलवार को किरण नेत्रालय सेवा समिति फुलवरिया बाजार कैड़ीबाड़ी बरौनी के सौजन्य से किरण नेत्रालय अस्पताल में पिछले कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी डॉक्टर्स डे के अवसर पर निःशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आंख के बीमारी से परेशान 175 रोगियों की आंख जांच किया गया। इस सिलसिले में किरण नेत्रालय के डायरेक्टर व आंख रोग विशेषज्ञ डॉ. अजीत कुमार ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से डॉक्टर्स डे के मौके पर हर साल गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आंख जांच कैंप का आयोजन किया जाता है। इसलिए इस वर्ष भी किरण नेत्रालय सेवा समिति आंख जांच का निशुल्क कैंप लगाया है। कैंप में आए रोगियों को आंख जांच करने के बाद मुफ्त में दवा चश्मा इत्यादि दी गई।

वही अजित कुमार ने बताया कि जो रोगी मोतियाबिंद से पीड़ित हैं। वैसे रोगियों को चिन्हित कर किरण नेत्रालय बुलाया गया है। जिनका आंख का ऑपरेशन जरूरी है, ऐसे मरीजों को कम खर्च पर ऑपरेशन की सहूलियत मुहैया कराई जाएगी। सुलभ तरीका से लैंस वाली ऑपरेशन करके ठीक किया जाएगा। डॉ. अजीत कुमार ने कहा कि उक्त अस्पताल बरौनी में कंप्यूटराइज आंख जांच नेपाल की तरह बिना टाका का लेंस वाली मोतियाबिंद ऑपरेशन, प्रत्येक गुरुवार और रविवार को प्रातः 9:00 बजे से 3:00 बजे तक किया जाता है। मोतियाबिंद के रोगियों को मुफ्त में दवा, काला चश्मा, भोजन और ठंड के मौसम में कंबल भी दी जाती है।

गौरतलब हो कि किरण नेत्रालय सेवा समिति के द्वारा गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, दुर्गा पूजा, डॉक्टर्स डे जैसे प्रमुख पर्व-त्योहारों के अवसर पर हर वर्ष आंख जांच का निःशुल्क कैंप की जाती है। इस तरह का मुफ्त आंख जांच शिविर आयोजन करने से इलाके के गरीबों को बहुत फायदा होता है। शिविर को सफल बनाने में ऑप्टोमेट्री रितिककुमार, सोनाली भारती, इंद्रजीत मिश्रा, त्रिलोकीनाथ, मिंटू पासवान, आरती कुमारी, बादल कुमार, डॉ. बासु, डॉ. ओम कुमार, राहुल, ईशान एवं सभी किरण नेत्रालय सेवा समिति के कर्मचारी का सहयोग सराहनीय रहा।

हरियाणा का लिंगानुपात बढ़कर हुआ 906

एसीएस ने लिंगानुपात सुधारने के लिए एसटीएफ की साप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता की

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा में लिंगानुपात सुधारने के लिए नए सिरे से प्रयास करते हुए स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्यव्यापी 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत, राज्य भर के सार्वजनिक पार्कों में जागरूकता रैलियां और मार्च आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक रैली में संबंधित जिले के लिंगानुपात को दर्शाने वाले बैनर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना और बालिकाओं के महत्व के सामाजिक संदेश को मजबूत करना है।

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग भी संदेश को और अधिक बढ़ाने के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों के सोशल मीडिया हैंडल पर समर्पित अभियान चला रहा है। ऐसे लगातार प्रयासों से, हरियाणा का लिंगानुपात 1 जनवरी से 30 जून, 2025 की अवधि के दौरान 906 तक सुधर गया है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 904 था। यह जानकारी आज यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के लिए राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) की साप्ताहिक बैठक के दौरान दी गई। बैठक में अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने और 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत राज्य के लिंगानुपात में और अधिक सुधार करने के प्रयासों को तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अवैध गर्भपात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया, साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे इसमें शामिल पाए जाने वाले किसी भी डॉक्टर के लाइसेंस रद्द करने सहित सख्त दंडात्मक कार्रवाई करें।

ऐसे ही एक हालिया मामले में, हिसार के एक अस्पताल का एमटीपी (गर्भावस्था का चिकित्सा समापन) लाइसेंस अवैध गर्भपात गतिविधियों के लिए रद्द कर दिया गया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में जन्म पंजीकरण शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया और इन अभियानों के बारे में निवासियों को सूचित करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान की आवश्यकता पर बल दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी अपंजीकृत बच्चों को आधिकारिक प्रणाली में लाया जाए।

श्री सुधीर राजपाल ने संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों (आईसीडीएस) को अगले सप्ताह तक स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परामर्श से अपंजीकृत बच्चों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) की बढ़ी हुई निगरानी पर जोर दिया और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (एसएमओ) को उनके अधिकार क्षेत्र में रिपोर्ट की गई किसी भी अवैध प्रथा के लिए जवाबदेह ठहराया। उन्होंने चेतावनी दी कि गैर-अनुपालन करने वाले एसएमओ को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उनके स्टेशन छोड़ने पर रोक लगाना भी शामिल है, और ऐसे अधिकारियों के लिए एक ब्लैकलिस्ट बनाने का निर्देश दिया। अधिकारियों को पीजीटी (प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग) करने वाले और लिंग-निर्धारण गतिविधियों में लिप्त संदिग्ध आईवीएफ केंद्रों पर निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने लिंगानुपात में पिछड़ रहे जिलों में कार्रवाई और छापेमारी तेज करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सीमा पार लिंग-चयनात्मक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के साथ अंतर-जिला समन्वय को मजबूत करने का आह्वान किया, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां निवासी हरियाणा के बाहर ऐसी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं से जुड़ी सहेलियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो सुरक्षित और सफल प्रसव सुनिश्चित करती हैं। दूसरी ओर, गर्भपात के मामलों से जुड़ी सहेलियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक श्री रिपुदमन सिंह ढिल्लों और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

भारत के धरोहर हैं वरिष्ठ पत्रकार पद्मभूषण रामबहादुर राय: मनीष कुमार शेखर

पद्मभूषण रामबहादुर राय को जन्मदिन की बधाई देते हुए मनीष शेखर ने संक्षिप्त जीवनवृत्त की दी जानकारी

संजना भारती संवाददाता

स्वर्णिम भारत निर्माण के अध्यक्ष मनीष कुमार शेखर ने महान विचारक, चिंतक, वरिष्ठ पत्रकार एवं भारत सरकार के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के अध्यक्ष पद्मभूषण रामबहादुर राय को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से उनके स्वस्थ्य एवं दिघार्यु जीवन की कामना की है।

शेखर ने पद्मभूषण रामबहादुर राय की संक्षिप्त जीवनवृत्त की जानकारी देते हुए बताया कि पद्मभूषण रामबहादुर राय हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार, चिंतक एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में वे देश की सबसे पुरानी (1948 में स्थापित) बहुभाषी न्यूज एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार के समूह संपादक हैं। वे हिन्दुस्थान समाचार के ही साप्ताहिक 'युगवार्ता' और मासिक 'नवोत्थान' के भी समूह सम्पादक हैं। पद्मभूषण रामबहादुर राय देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में कॉलम लिखते रहे हैं, जो बहुत चर्चित हुए।

जीवन परिचय: पद्मभूषण रामबहादुर राय का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के सोनाड़ी गांव में 1 जुलाई 1946 को हुआ था। उनकी कक्षा पांच तक की शिक्षा पश्चिम बंगाल के मालदह में हुई थी। इसके बाद कक्षा छह से आठ तक की शिक्षा निकटवर्ती गांव अवथही के पूर्व माध्यमिक विद्यालय से प्राप्त करने के बाद रामबहादुर ने दसवीं तक की शिक्षा एसएमएन इंटर कालेज मच्छटी से ग्रहण की। 12 वीं की पढ़ाई के लिए वो गाजीपुर चले आए जहां एमएच इंटर कालेज से उन्होंने इंटमीडिएट पास किया। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने बनारस के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया जहां से उन्होंने स्नातक करने के पश्चात अर्थशास्त्र में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। राम बहादुर राय छात्र जीवन से ही राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ गए थे।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए, एमए और ला करने के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन को मजबूत करने में लगे रहे। 1965 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदू शब्द हटाने के विरोध में राम बहादुर राय ने जोरदार आंदोलन चलाया। 1971 में वीसी कालूलाल श्रीमाली के खिलाफ आंदोलन छेड़ने पर 46 छात्र नेता निष्कासित कर दिए गए। निष्कासन वापसी की शर्त माफी माँगनी रखी गई। 44 नेताओं ने माफी माँग ली किंतु दो ने नहीं माँगी। उन दो में एक राम बहादुर राय थे, दूसरे मार्कंडेय सिंह। तब राम बहादुर राय अर्थशास्त्र में बीएचयू में पीएच.डी. कर रहे थे। राय साहब वर्धा जाकर विनोबा भावे से मिले किंतु कोई लाभ न हुआ और उनके शोध का काम अधर में लटक गया।

1971 में बनारस में जेपी के एक भाषण से प्रेरित होकर रामबहादुर राय पूर्वी बंगाल गए और वहाँ से लौटकर मुक्ति संग्राम का आँखों देखा हाल 'आज' अखबार के 5 मई 1971 के अंक में लिखा। उन दिनों बनारस में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सभा रखी गई। छात्र संघों पर रोक के खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने उन्हें काला झंडा दिखाने का फैसला किया। इंदिरा जी की सभा में मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह भी आए थे। रामबहादुर राय ने काला झंडा दिखाया। गिरफ्तार किए गए। राम बाहदुर राय को विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। बिहार में संगठन को मजबूत बनाने का दायित्व उन्हें दिया गया। राय साहब ने पूरे बिहार में घूम-घूम कर विद्यार्थी परिषद का संगठन खड़ा किया। एक वर्ष की कड़ी मेहनत रंग लाई। पटना छात्र संघ का चुनाव हुआ। लालू प्रसाद अध्यक्ष, सुशील मोदी महासचिव और रवि शंकर प्रसाद सचिव चुने गए। 1974 में छात्र संघर्ष समिति बनी। विधानसभा घेराव का कार्यक्रम बना। राय साहब गिरफ्तार किए गए। मीसा में वह पहली गिरफ्तारी थी। दस महीने जेल में रहे। इमरजेंसी में भी राय साहब गिरफ्तार कर लिए गए और 16 महीने जेल में रहे। जेल से छूटे तो सक्रिय राजनीति के बजाय पत्रकारिता का चयन किया।

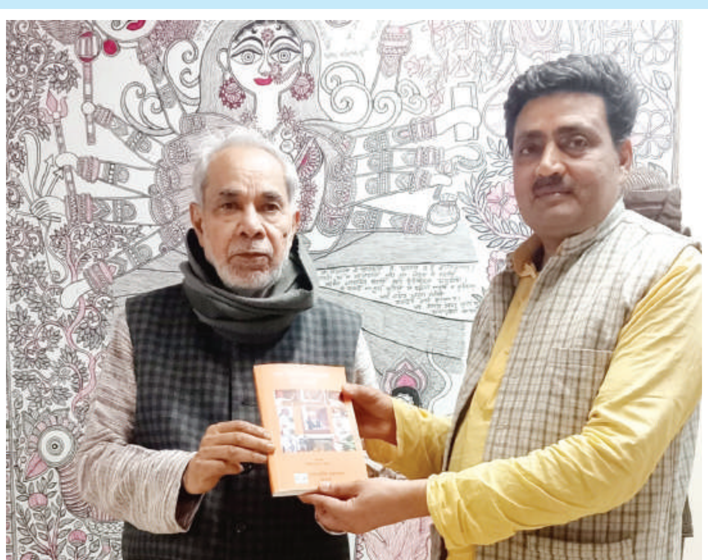

पत्रकारिता का सफर: राम बहादुर राय ने 1979 में हिंदुस्तान समाचार एजेंसी से पत्रकारिता प्रारंभ की। 1983 में दिल्ली से 'जनसत्ता' शुरू हुआ तो उसके स्थापना काल से ही राम बहादुर राय जुड़ गए। सालभर बाद ही उन्हें चीफ रिपोर्टर बना दिया गया। उन्हीं दिनों राजेन्द्र माथुर 'नवभारत टाइम्स' के संपादक बनकर दिल्ली आ गए थे। वे राय साहब को अपने यहाँ बुलाते रहे। 1986 में राय साहब 'नवभारत टाइम्स' में विशेष संवाददाता बनकर चले गए। राय साहब को प्रभाष जोशी बहुत मानते थे। इसलिए उनसे कहते रहते - 'जनसत्ता' में लौट आओ। तुम्हारा अखबार 'जनसत्ता' है। 1991 में राय साहब 'जनसत्ता' में लौट आए। 1994-95 तक 'जनसत्ता' के ब्यूरो चीफ रहे। 1995 से 2004 तक वे 'जनसत्ता' के संपादक (समाचार सेवा) रहे। राय साहब को भाजपा ने लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए दो-दो बार प्रस्ताव दिया किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्हें राज्यसभा में भी भेजने की पेशकश की गई लेकिन उसे भी उन्होंने ठुकरा दिया।

उपलब्धियां: एक पत्रकार के तौर पर राय के चलते ही हवाला घोटाला सुर्खियों में आया था। राम बहादुर राय की कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर 'रहबरी के सवाल', पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह पर 'मंजिल से ज्यादा सफर' और आचार्य जे. बी कृपलानी की जीवनी 'शाश्वत विद्रोही: आचार्य जे बी कृपलानी' नामक पुस्तकें शामिल हैं।

जेपी आंदोलन के संगठनकर्ता: जेपी आंदोलन के संस्थापक संगठनकताओं में एक राम बहादुर राय भी थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सहयोगी रह चुके राय ने 1974 के छात्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभायी थी। वे जेपी आंदोलन की ग्यारह सदस्यीय छात्र संघर्ष संचालन समिति के सदस्य थे। राम बहादुर राय के नेतृत्व में ही लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद इत्यादि छात्र नेता जयप्रकाश नारायण से मिले और उन्हें आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए न सिर्फ आमंत्रित किया बल्कि उनकी सहमति भी हासिल की। 1977 के आम चुनाव में राम बहादुर राय को लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट ऑफर किया गया लेकिन रामबहादुर राय ने सक्रिय राजनीति में आने की बजाय पत्रकारिता को अपना करियर चुना।

आपातकाल में पहली गिरफ्तारी: राय वो पहले व्यक्ति थे, जिन्हें अप्रैल 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (मीसा) के तहत गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनकी रिहाई हुई। बाद में आपातकाल के दौरान उन्हें दूसरी बार गिरफ्तार किया गया और वे 16 महीनों तक जेल में रहे। इसके पहले वे 1974 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सचिव थे।

सम्मान एवं पुरस्कार: रामबहादुर राय को पत्रकारिता के जरिए उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पद्मभूषण एवं 'पद्म श्री' सम्मान दिया गया। हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें माधवराव सप्रे पत्रकारिता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भोपाल में आयोजित समारोह में मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैलाश जोशी ने श्रीराय को ये सम्मान प्रदान किया।

पद्मभूषण
पद्म श्री
माधवराव सप्रे पत्रकारिता पुरस्कार
माणिकचन्द्र वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार
भगवान दास जनजागरण पत्रकारिता पुरस्कार
पत्रकारिता पुरस्कार, हिन्दी अकादमी, दिल्ली
सत्याग्रही सम्मान, जयपुर
पत्रकारिता सम्मान, विकल्प
जगदगुरु रामानंदाचार्य पुरस्कार, 2015

पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर वृक्षारोपण किया गया

एसबी ब्यूरो प्रमुख/इन्तजार हुसैन

बदायूं। पूर्व नगर अध्यक्ष मुख्तार अहमद बाबा के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी यूथ के राष्ट्रीय सचिव अली अल्वी ने पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर हाइवे पर वृक्षारोपण कर जन्मदिन मनाया और उनकी लम्बी आयु की दुआऐं की। इस मौके पर जाहिद गाजी, अंजर खान, जीशान फारूकी, नरेश, मुकेश ठाकुर, फिरोज अल्वी, सब्बू खान, शान अल्वी, साधु सिंह, वाहिद अल्वी, शालिम, रुमी अंसारी, संजीव आदि लोग मौजूद रहे।

मुहर्रम को लेकर मंसूरचक थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित

एसबी ब्यूरो

मंसूरचक। मंसूरचक थाना में मंगलवार को मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता बीडीओ सुभाष कुमार ने की। जबकि संचालन एसआइ कविता कुमारी ने किया। बैठक में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी व ताजिया समिति के सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान मुहर्रम शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का निर्णय लिया गया। बीडीओ ने सभी अखाड़ा के लोगों से सरकारी गाइडलाइन के अनुसार मुहर्रम मनाने की बात कही। उन्होंने अफवाहों से लोगो को बचने की बात कही।

एसआइ कविता कुमारी ने कहा कि त्योहार के दौरान शांति भंग करनेवालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। मौके अंचलाधिकारी सुजीत कुमार सुधन, एसआइ रामप्रवेश तिवारी, मुखिया संघ के अध्यक्ष इजहार अंसारी, समाजिक कार्यकर्ता आलोक मिश्रा, सत्यनारायण महतो, सुनील कुमार, मो. सलामत, पूर्व मुखिया प्रमोद महतो, धर्मवीर सिंह कुंदन, पवन पोद्दार, मो. जावेद, भोला शर्मा, रंजीत महतो, ललित कुमार, क्रांति कुमारी, सोनी देवी, राजेश कुमार सहित अन्य कई लोग उपस्थित थे।

मुख्य विकास अधिकारी ने स्कूल चलो अभियान रैली को विद्यालय से हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

संजना भारती संवाददाता/मनोज कुमार बिन्द

जिलाधिकारी महोदय के कुशल निर्देशन में स्कूल चलो अभियान कार्यकम का आरम्भ मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा मंगलवार को कम्पोजिट विद्यालय आदर्श एलनगंज, नगर क्षेत्र में नव प्रवेशित छात्रों को माला पहनाकर, रोली, टीका लगाकर उत्साहवर्धन किया गया तथा निशुल्क पुस्तके एवं स्टेशनरी वितरण करते हुए शिक्षको एवं अभिभावको को अधिक से अधिक संख्या में नामांकन कराने हेतु प्रेरित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने स्कूल चलो अभियान रैली को विद्यालय से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण एवं मातृत्व के महत्व को दशार्ते हुए एक पेड मॉ के नाम कार्यक्रम के अन्तर्गत पौधरोपण कर स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के द्वितीय चरण का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर श्री देवव्रत सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, श्रीमती प्रतिभा सिंह, खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र, खण्ड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, जिला समन्वयक एम०डी०एम०, जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता सहित समस्त जिला समन्वयक, विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं स्काउट गाइड की टीम मौजूद रही।

उल्लेखनीय है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा, एवं राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ के द्वारा ग्रीष्मावकाश के पश्चात विद्यालय पुनः खुलने पर नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं का स्वागत एवं स्कूल चलो अभियान (द्वितीय चरण) दिनांक 01 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक के किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसमें विद्यालय पुनः खुलने पर विद्यालय परिसर की समुचित साफ-सफाई कराते हुए विद्यालय को सुन्दर एवं आकर्षक बनाने, विद्यालय परिवार द्वारा छात्र-छात्राओं का स्वागत करने तथा इसे एक उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने के कहा गया है।

इस प्रकार के कार्यक्रम से छात्र-छात्राओं का विद्यालय के प्रति तथा विद्यालय के अध्यापकों के प्रति जुडाव पैदा होगा, जिसके फलस्वरूप विद्यालय में उनकी नियमित उपस्थिति तथा पठन-पाठन गतिविधियों में सक्रियता एवं रूचि उत्पन्न होगी। विद्यालय को फूल, पत्तों, रंगोली, झंडियों, गुब्बारों आदि से सजाया जाये और विद्यालय आने वाले बच्चों को रोली-टीका लगाकर स्वागत किया जाये। उस दिन मध्याहन भोजन में बच्चों के लिए रूचिकर हलवा, खीर आदि बनाया जाये। तत्कम में जनपद के सभी परिषदीय विद्यालय में बच्चों का स्वागत कार्यक्रम उत्सव की भांति आयोजित किया गया एवं बच्चों के लिए रूचिकर हलवा, खीर आदि मीनू के अनुसार बनाया गया।इस कार्यक्रम में स्कूल चलो अभियान के द्वारा विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि तथा नामांकित छात्र-छात्राओं की नियमित उपस्थिति बढ़ाने के लिए समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

विद्यालय द्वारा क्षेत्र में बच्चों की रैली निकाल कर विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों तथा शत-प्रतिशत नामांकन एवं नियमित उपस्थिति के लिये जनमानस को जागरूक किया जाएगा। मुनादी, उद्घोषणा एवं प्रभावशाली व्यक्तियों से स्थानीय स्तर पर अपील जारी कर नामांकन एवं नियमित उपस्थिति हेतु माता/पिता/ अभिभावक/ समुदाय को जागरूक व प्रेरित किया जाएगा। बालिकाओं के शत प्रतिशत नामांकन एवम् उपस्थिति पर विशेष फोकस किये जाने तथा मीना मंच के बच्चों द्वारा विद्यालय स्तर पर नाटक का मंचन एवं आधा-फुल कॉमिक्स पर आधारित कहानियों का वाचन व चर्चा करायी जाएगी। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन/ नामांकन में मलिन बस्तियों, झुग्गी-झोपडियों, रेलवे स्टेशन के पास, ओवरब्रिज के नीचे अस्थायी आवास में रहने वाले परिवारों, परम्परागत कुटीर एवं लघु/सूक्ष्म उद्यमों में तथा ईंट-भट्ठों पर कार्यरत परिवारों तथा जनजाति एवं घुमन्तु समुदायों पर विशेष फोकस किया जाए।

अनुसूचित व पिछड़ा वर्ग की धर्मशालाओं में 75 प्रतिशत अनुदान पर लगेंगे सोलर पैनलः एडीसी सोनू भट्ट

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। एडीसी सोनू भट्ट ने कहा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग व हरेडा के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण एवं सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्लांट लगाने की योजना चलाई जा रही है। इसी योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा जिला की पंजीकृत अनुसूचित व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं में 75 प्रतिशत अनुदान पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्लांट लगाये जाएंगे जिसकी 25 प्रतिशत राशि सम्बंधित संस्था द्वारा वहन की जाएगी। इन धर्मशालाओं में बिना बैटरी बैंक के 5 किलोवाट तक के सोलर पॉवर प्लांट लगाये जायेंगे।

एडीसी सोनू भट्ट आज एडीसी कार्यालय में जिला की अनुसूचित व पिछड़ा वर्ग की धर्मशालाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सरकारी एवं गैर सरकारी गुरुकुल, कामकाजी महिला छात्रावास, अनाथालय, वृद्ध आश्रमों, बालगृह, नारी निकेतन, प्राकृतिक चिकित्सालय, रेडक्रॉस संस्थान तथा धर्मार्थ संस्थानों पर 50 प्रतिशत अनुदान पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्लांट लगाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी 50 प्रतिशत राशि सम्बंधित संस्था द्वारा दी जाएगी और इन संस्थानों में बिना बैटरी बैंक के 50 किलोवाट तक के सोलर पॉवर प्लांट लगाये जायेंगे। एडीसी ने कहा कि इच्छुक सामाजिक संस्थाएं नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होनी अनिवार्य हैं।

अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा न0 16, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय करनाल में सम्पर्क कर सकते हैं।

हरियाणा का लिंगानुपात बढ़कर हुआ 906

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। हरियाणा में लिंगानुपात सुधारने के लिए नए सिरे से प्रयास करते हुए स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्यव्यापी 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत, राज्य भर के सार्वजनिक पार्कों में जागरूकता रैलियां और मार्च आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक रैली में संबंधित जिले के लिंगानुपात को दशार्न वाले बैनर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना और बालिकाओं के महत्व के सामाजिक संदेश को मजबूत करना है। इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग भी संदेश को और अधिक बढ़ाने के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों के सोशल मीडिया हैंडल पर समर्पित अभियान चला रहा है। ऐसे लगातार प्रयासों से, हरियाणा का लिंगानुपात 1 जनवरी से 30 जून, 2025 की अवधि के दौरान 906 तक सुधर गया है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 904 था। यह जानकारी यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के लिए राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) की साप्ताहिक बैठक के दौरान दी गई।

कैथल मैराथन को लेकर तैयारियां पूरी रखें अधिकारीः डीसी प्रीति

मैराथन के सफल एवं भव्य आयोजन लिए कमेटी का किया गठन

संजना भारती संवाददाता

कैथल। डीसी प्रीति ने कहा कि आगामी 13 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी कैथल में मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अधिकारी इस मैराथन 2025 को लेकर सभी समय रहते अपनी तैयारियां पूरी करें। जल्द से जल्द मुख्य कार्यक्रम स्थल और मैराथन के लिए रूट प्लान फाइनल किया जाए, ताकि उसके अनुसार व्यवस्था की जा सके।

इसके साथ ही सभी अधिकारी अपने अपने विभाग के सभी अधीनस्थ कर्मचारियों, स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों, सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवकों व आमजन के ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं। साथ ही स्वयं सेवी संस्थाएं, प्रगतिशील किसान, युवा, जिले में कुछ विशेष करने वाले समूह इस मैराथन में बढ़चढ़ कर भाग लें। मैराथन रूट पर अपनी कला व कोई विशेष हुनर है तो उसके प्रदर्शन के लिए स्टॉल लगा सकते हैं। डीसी प्रीति लघु सचिवालय के वीडियो कांफ्रेंस रूम में चंडीगढ़ से आयोजित वीसी के उपरांत संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहीं थीं। उन्होंने कहा कि आगामी 13 जुलाई को ड्रग फ्री हरियाणा थीम पर आधारित कैथल हॉफ मैराथन को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। इस कार्यक्रम के सफल एवं भव्य आयोजन के लिए एडीसी दीपक बाबूलाल करवा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। एडीसी, एसडीएम कैथल, डीएसपी हेड क्वार्टर तथा डीएसपी ट्रैफिक की संयुक्त कमेटी मौके का निरीक्षण करके रूट निर्धारित करेगी। मैराथन में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोई भी आमजन www.kaithalhalfmarathon.com वेबसाइट पर जाकर तथा स्कैनर के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने शिक्षा विभाग, जिला उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला खेल अधिकारी को निर्देश दिए कि वे स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों व खिलाड़ियों का ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण करवाएं और हर रोज की प्रगति रिपोर्ट भी उपायुक्त कार्यालय को भिजवाएं। उन्होंने जिला प्रौद्योगिकी अधिकारी को निर्देश दिए कि पोर्टल में वरिष्ठ नागरिकों के पंजीकरण के लिए भी अलग से प्रावधान किया जाए।

एसपी आस्था मोदी ने मैराथन के सफल आयोजन के लिए सुरक्षा एवं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर एडीसी दीपक बाबूलाल करवा, डीएमसी सुशील कुमार, एसडीएम अजय सिंह, सीटीएम गुरविंद्र सिंह, डीएसपी बीरभान, डीएसपी सुशील प्रकाश, डीएसपी गुरविंद्र सिंह, जिला उच्च शिक्षा अधिकारी डा. मनोज कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी डा. नरेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

निर्वाचित महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। राज्य पंचायत संसाधन केंद्र, नीलोखेड़ी में विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा की और से 1 से 4 जुलाई तक पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सक्षम बनाने के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी योजना एवं प्रबंधन विकास विशेषज्ञ डॉ. नीलम छिक्कारा को पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा दी गई है। कार्यक्रम में निर्वाचित महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए राज्यभर से महिला ट्रेनरों को शामिल किया गया है। प्रशिक्षण के संपन्न होने के उपरांत महिला मास्टर ट्रेनरों के द्वारा स्थानीय स्वशासन की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने व सक्षम नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित के साथ शुरू किया गया। इस मौके पर कोर्स कॉर्डिनेटर डॉ. नीलम छिक्कारा, संकाय सदस्य डिम्पी मल्होत्रा, फतेहाबाद के ग्राम पंचायत गदली सुनीता देवी सरपंच, जिला फरीदाबाद के ग्राम पंचायत फतेहपुर की सरपंच सरोज रानी सरपंच, बिल्लोच स्टेट मास्टर ट्रेनर सुमन लता, पूनम व नेहा डीपीएम चरखी दादरी आदि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 मार्च 2025 को एक मॉड्यूल बदलाव का नेतृत्व की शुरूआत पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों को स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सुशासन और उससे परे महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने के लिए की।

इस कार्यक्रम के अवसर पर कोर्स कोआर्डिनेटर डॉ. नीलम छिक्कारा ने प्रथम सत्र के दौरान प्रतिभागियों को बताया कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली विभिन्न नीतियों के बावजूद राजनीतिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी बहुत सीमित है। देश में महिला आरक्षण लागू होने से सुशासन में महिलाओं की संख्या तो बढ़ी लेकिन उनकी आवाज अभी भी कमजोर बनी हुई है। केवल राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की मौजूदगी इस बात की गारंटी नही देती कि उनकी मांगे, आवश्यकताएं और हित राजनीति और नीतियों में प्रभावी रूप से शामिल कर लिए जाएं। महिला नागरिकों और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के बीच जुड़ा की कमी नीतियों और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं के प्रभाव को सीमित कर देती है। प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन और सर्वेक्षण दोनों इस बात को महसूस कराते हैं कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की जरूरत है ताकि वे सरपंच एवं पंच के रूप में अपने अधिकारों का सही उपयोग कर सके।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिकार प्राप्त पदों पर आने और अपनी जिम्मेदारी संभालने के दौरान घर परिवार और समाज में कई तरह की बढ़ाओ का सामना करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें ऐसे कौशल सिखाए जायें, कि वे अपनी व्यक्तिगत और आधिकारिक भूमिकाओं को बेहतर तरीके से निभा सके। साथ ही, उन्हें पंचायत राज व्यवस्था की पूरी समझ होनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। इस चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में अलग-अलग गतिविधियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इतनी सारी गतिविधियां पहली बार किसी ट्रेनिंग में करवाई जा रही हैं ताकि महिला ट्रेनर महिला सरपंचों के साथ अच्छे से तालमेल बनाकर उन्हें अच्छे से समझा पाए और उनमें हौंसला भर सके कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभा सकती हैं।

इस कार्यक्रम के दौरान पंचायत एवं विकास विभाग की मीडिया की टीम की तरफ से श्री वेदांश और विवेक भी सम्मिलित रहे।

खुशहाल माजरा, नानकपुर, बुबकपुर, अंगौध व खानपुर में डोर टू डोर अभियान चलाकर आमजन को नशा ना करने बारे किया जागरूक

संजना भारती संवाददाता

कैथल। नशा मुक्त हरियाणा मुहिम के तहत समाज को नशा मुक्त करने के उद्देश्य से एसपी आस्था मोदी के निदेर्शानुसार चलाई जा रही मुहिम तहत पुलिस टीम द्वारा कैथल जिले में आमजन को नशे के दुष्परिणामों बारे लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी मुहिम तहत जागरूकता टीम में शामिल एसआई कर्मबीर, एएसआई ओमप्रकाश, एचसी सुनील कुमार, महिला सिपाही किस्मत, एसपीओ राजपाल तथा एसपीओ प्रदीप कुमार की टीम द्वारा डोर टू डोर अभियान चलाकर खुशहाल माजरा, नानकपुर, बुबकपुर, अंगौध व खानपुर में मौजिज व्यक्तियों सहित आमजन को नशे के प्रति जागरूक करने के साथ साथ इस अभियान को सफल बनाने में आमजन से सहयोग की अपील की है।

डीएसपी कुलदीप बेनीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह टीम गांव गांव जाकर हर दिन कार्यक्रम कर रही है। आमजन भी इस मुहिम में पुलिस का साथ दे रहे है तथा पुलिस की इस कल्याणकारी मुहिम की प्रशंसा कर रहे है। डीएसपी ने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है, जो नशा किसी के लिए भी हितकारी नहीं हो सकता। नशे की लत में पड़ गया व्यक्ति अपने दृढ संकल्प से इस बुराई को छोड़ सकता है। पुलिस द्वारा जहां पर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं पर पुलिस द्वारा नशे के आदि व्यक्ति का नशा छुडवाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा जिले में नशे से पीड़ित व्यक्तियों की काउंसलिंग करवाई जा रही है।

डीएसपी ने कहा कि युवावर्ग को भी खेल या अन्य गतिविधि में बेहतरीन कार्य करके अपने माता पिता, गांव समाज का नाम रोशन करना चाहिए। नशा मुक्त व अपराध मुक्त समाज की स्थापना के लिए हम सभी को मिलकर कदम उठाने होंगे। पुलिस मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई कर रही है। मगर लोगों में नशा के खिलाफ जागरूकता पैदा करने तथा इस अभियान की शत प्रतिशत सफलता के लिए जन सहयोग अति आवश्यक है। आमजन नशे से संबंधित कोई भी सूचना पुलिस को दे। सूचना देने वाले का नाम पता गुप्त रखा जाएगा।

कम लिंगानुपात वाले गांवों में लिंगानुपात में सुधार की रणनीति तैयार करें स्टैंडिंग कमेटी के अधिकारी-डीसी प्रीति

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। डीसी प्रीति ने कहा कि जिले में लिंगानुपात में सुधार के लिए सभी संबंधित विभाग टीम वर्क के साथ काम करें। स्टैंडिंग कमेटी के सभी सदस्य जिले में लिंग जांच एवं भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए रणनीति तैयार करें। जिन गांव में लिंगानुपात खराब है, उन गांव में विशेष फोकस किया जाए। सबसे कम लिंगानुपात वाले गांवों में गर्भपात जैसे तथ्यों का विश्लेषण करें, लिंगानुपात कम होने का असली कारण पता लगाकर जमीनी स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाए। बेटी बचाओ-बेटी बचाओ अभियान के तहत गांव में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता कैंप लगाए जाएं। आशा वर्कर व आंगनबाड़ी वर्कर निगरानी रखें और गर्भवती महिलाओं का डाटा अपडेट रखें। पुलिस विभाग लिंग जांच के केस में सख्त कार्रवाई करते हुए उदाहरण पेश करें, ताकि कोई इस प्रकार का कृत्य न करें।

डीसी प्रीति मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में जिला स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहीं थीं। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि जिले में स्थित अल्ट्रासाउंड सेंटर, एमटीपी सेंटर तथा आईवीएफ सेंटरों की निगरानी रखें और उनका समय समय पर औचक निरीक्षण किया जाए। जिला ड्रग कंट्रोलर सुनिश्चित करें कि जिले में कहीं भी अवैध रूप से एमटीपी किट नहीं बेची जाए। समय-समय पर मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया जाए। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गांव में जागरूकता कैंप आयोजित किए जाएं, जिनमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, महिला बाल विकास विभाग तथा ग्राम पंचायत को शामिल किए जाए। महिला बाल विकास विभाग यह सुनिश्चित करें कि आशा वर्कर एवं आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा गांव में गर्भवती महिलाओं का डाटा अपडेट रखें। सभी पुलिस थानों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुझाव पेटिका लगाई गई है, आशा वर्कर व आंगनबाड़ी वर्कर लिंग जांच या भ्रूण हत्या आदि की गुप्त जानकारी सुझाव पेटिका में डाल सकते हैं।

डीसी प्रीति ने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि हर माह स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाए और लिंगानुपात की प्रगति के बारे में विचार विमर्श किया जाए।

लघु सचिवालय में भी एक सुझाव पेटिका लगाई जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति लिंग जांच से संबंधित गुप्त जानकारी दे सके। इसके साथ ही लघु सचिवालय में बेहतर लिंगानुपात और कम लिंगानुपात वाले गांव की सूची को प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाल ही में एमटीपी किट के संबंध में दर्ज एफआईआर में सख्त कार्रवाई करें। ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि कन्या भ्रूण हत्या कानूनी अपराध है। उन्होंने एक-एक करके कम लिंगानुपात वाले गांवों को लेकर समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।

इस अवसर पर सिविल सर्जन डा. रेणु चावला, डीएसपी सुशील प्रकाश, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी नसीब सिंह सैनी, महिला बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी शशि, जिला ड्रग कंट्रोलर डा. चेतन वर्मा, सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी अमित कौशिक तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रतिनिधि मौजूद रहे।

सफाई अपनाओ-बीमारी भगाओ अभियान शुरूः विद्यार्थियों और बस्तीवासियों को किया गया जागरूक

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। नगर निगम करनाल ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरूआत कर दी है। यह विशेष स्वच्छता अभियान 31 जुलाई 2025 तक चलेगा। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि यह अभियान केन्द्रीय शहरी एवं आवासन मामले मंत्रालय के निदेर्शों के तहत चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को साफ-सफाई के प्रति जागरूक कर डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव सुनिश्चित करना है।

अभियान के पहले दिन मंगलवार को निगम की स्वच्छ भारत मिशन-शहरी टीम के ट्रीगर मास्टर और मोटीवेटरों ने मॉडल टाऊन स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और मंगल कॉलोनी स्थित डेहा बस्ती में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। साथ ही संबंधित बीट के दरौगाओं व सुपरवाइजरों ने घर-घर जाकर कूलरों और नालियों की सफाई की जांच की।

ट्रीगर मास्टर गुरदेव सिंह ने विद्यार्थियों और बस्तीवासियों को बताया कि डेंगू व मलेरिया से बचने के लिए छतों, कूलरों व नालियों की नियमित सफाई आवश्यक है। मच्छरों के लारवे को न पनपने देना ही बीमारी से बचाव का मूल उपाय है। उन्होंने नागरिकों को सलाह दी कि वे मलेरिया रोधी दवा नजदीकी चिकित्सा केंद्र से लेकर सावधानीपूर्वक प्रयोग करें, लेकिन इसका छिड़काव पीने के पानी में न करें।

इस अवसर पर कष्ट निवारण समिति के सदस्य एवं डेहा बंगाली समाज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गोपी घारू, विद्यालय प्रधानाचार्य सुनील कुमार, अध्यापक जयवीर ढाकलां, बस्ती से बबन कंडारा, विनोद घारू, रिंकू मराड, चन्दन सारसर तथा मोटीवेटर कुलदीप, महेन्द्र व दीपमाला भी मौजूद रहे।

'एक पेड़-मां के नाम' मुहिम के तहत ब्रह्मकुमारी आश्रम राजौंद द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजौंद के सदस्य बीके आशा ने बताया कि आश्रम सेवको द्वारा मंगलवार, एक जूलाई को नगर के कैथल मार्ग पर "एक पेड़-मां के नाम" कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मकुमारी बहनों ने वृक्षों की महत्ता को बताते हुए कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रकृति हमें देतीं हैं। क्योंकि उनका काम है देना और सिर्फ देना। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी मां प्रकृति के संरक्षण के लिए अपना हाथ बढ़ाएं...चलो आज एक पौधा मां के नाम लगाएं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मकुमारी बहन ने कहा कि पौधा लगाना बडी बात नहीं बल्कि उसे संभालना जरूरी है।

समाजसेवी अशोक कुमार ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। प्रकृति हमें पूरी उम्र देती है, लेती कुछ भी नहीं है। आज ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता जा रहा है। मानव यदि नेचर के लिए कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम पौधारोपण करके प्रकृति का आभार प्रकट करें। भेजें संदेश में बीके नीलम व बीके सरीता ने बताया कि मानव को चाहिए कि जीवन में जो भी अच्छे दिवस आते हैं जैसे कि जन्मदिन, एनिवर्सरी इत्यादि इन पर पौधारोपण करें। ताकि हम वातावरण में संतुलन बनाने में सहयोग कर सके। भ्राता राममेहर ने भेजे संदेश में कहा कि एक व्यक्ति, समाज को सिर्फ 80 से 100 सालों तक कुछ दे सकता है। परंतु वृक्ष कई पीढियां तक मानव व समाज की सेवा करते हैं। इसीलिए वृक्षों का ज्यादा से ज्यादा रोपण करना चाहिए।

राजौंद में इस कार्यक्रम के तहत ब्रह्माकुमारी भाई व बहनों ने पौधे लगाए तथा आमजन को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया।

इस आवसर पर बीके ऊषा ने अपने संदेश में मानव मात्र से अपील करते हुए कहा कि जितना हो सके सभी ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें, ताकि पर्यावरण को संजीवनी मिल सकें।

इस अवसर पर राजौंद नगर व क्षेत्र के ब्रह्मकुमारी आश्रम के दर्जनों स्वयं सेवक उपस्थित रहे।

लिंगानुपात बढ़ाने के लिए गांव पाई, कलायत, राजौंद में लगाया गया जागरूकता कैंप

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गांव पाई, कलायत, राजौंद के गावों में बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं अभियान का प्रचार किया गया। जिसमें मौके पर मौजूद सुपरवाईजर सोनिया ने गांव की सभी आंगनबाड़ी वर्करों को लिंगानुपात के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार लाना है। इससे समाज में लड़कियों के प्रति निहित भेदभाव से निपटना है तथा देश के नागरिकों की मानसिकता में बदलाव लाना है। उन्होंने बताया कि लिंगानुपात को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और कानूनी स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे है, जिसमें मुख्य रूप से महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इसके अलावा सामाजिक सोच में बदलाव लाना और लिंग चयन पर रोक लगाना भी महत्वपूर्ण है। बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं अभियान के माध्यम से सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने का प्रयास जारी है।

सामाजिक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को बेटियों के महत्व और समानता के बारे में भी शिक्षित किया जा सकता है। लिंग चयन को रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी अधिनियम जैसे कानून को सख्ती से लागू किया गया है। जिसके तहत अब हर गर्भवती माता पर नजर रखी जा रही है। अगर कोई भी गर्भवती स्त्री लिंग परीक्षण करवाती हुई पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सुपरवाईजर मंजू बंसल के द्वारा उधम सिंह पार्क में प्रातः कालीन जागरूकता अभियान चलाया गया।

इस मौक पर सुपरवाईजर सपना, दीप्ति, सीमा, सरिता, मंजू, बीरमती, मीनू, सुमन तथा आंगनवाड़ी वर्कर मीना कुमारी, सरोज रानी, रीना, मुकेश, सुशीला, कमलेश, भानवती, शीला, राजबाला, आशा मौजूद रही।